EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

26 JULY - 1 AUG 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques: The headquarters of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) is located in which city?
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?

A) Mumbai / मुंबई

B) New Delhi / नई दिल्ली

C) Gandhinagar (GIFT City) / गांधीनगर (गिफ्ट सिटी)

D) Hyderabad / हैदराबाद

E) Ahmedabad / अहमदाबाद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) is planning to establish an independent Arbitration Centre in GIFT City, Gujarat.

• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) गुजरात के GIFT City में एक स्वतंत्र मध्यस्थता (Arbitration) केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

• The proposed centre aims to improve the ease of doing business and provide a dedicated dispute resolution mechanism for financial institutions and businesses operating in GIFT City.

• प्रस्तावित केंद्र का उद्देश्य कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाना तथा GIFT City में कार्यरत वित्तीय संस्थानों एवं व्यवसायों के लिए समर्पित विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराना है।

• An expert committee has been constituted, and the proposal is currently under the Government's consideration.

• इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है तथा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

• The Arbitration Centre is expected to strengthen GIFT City as a leading international financial hub and improve its competitiveness with global financial centres such as Dubai and Hong Kong.

• यह मध्यस्थता केंद्र GIFT City को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में मजबूत

करेगा तथा दुबई और हांगकांग जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के साथ इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• International Financial Services Centres Authority (IFSCA) – Established: 27 April 2020
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) – स्थापना: 27 अप्रैल 2020
• Headquarters – GIFT City, Gandhinagar, Gujarat
• मुख्यालय – गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात
• Regulator for International Financial Services Centres (IFSCs) in India
• भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) का नियामक

Ques: ICICI Bank has raised how much through the largest single-tranche US dollar bond issue by an Indian issuer in 2026?
प्रश्न: ICICI बैंक ने 2026 में किसी भारतीय जारीकर्ता के सबसे बड़े सिंगल-ट्रांच अमेरिकी डॉलर बॉन्ड इश्यू के माध्यम से कितनी राशि जुटाई?

A) US$500 Million / 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर

B) US$750 Million / 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर

C) US$1 Billion / 1 अरब अमेरिकी डॉलर

D) US$1.5 Billion / 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर

E) US$2.3 Billion / 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• ICICI Bank has raised US$1 billion through a five-year senior unsecured US dollar bond, marking its first public US dollar bond issuance since 2017.
• ICICI बैंक ने 5-वर्षीय सीनियर अनसिक्योर्ड अमेरिकी डॉलर बॉन्ड के माध्यम से 1

अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यह 2017 के बाद बैंक का पहला सार्वजनिक अमेरिकी डॉलर बॉन्ड इश्यू है।

- It is the largest single-tranche US dollar bond issue by an Indian issuer in 2026.
- यह 2026 में किसी भारतीय जारीकर्ता द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा सिंगल-ट्रांच अमेरिकी डॉलर बॉन्ड इश्यू है।
- The bond was priced at 100 basis points above the 5-year US Treasury yield and carried a 5.46% coupon rate.
- इस बॉन्ड का मूल्य निर्धारण 5-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 100 बेसिस पॉइंट ऊपर तथा 5.46% कूपन दर पर किया गया।
- The issue received orders worth more than US$2.3 billion, reflecting strong demand from global investors.
- इस इश्यू को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं, जो वैश्विक निवेशकों की मजबूत मांग को दर्शाती हैं।
- The funds raised will be used for general corporate purposes under ICICI Bank's US$7.5 billion Global Medium Term Note (GMTN) Programme.
- जुटाई गई राशि का उपयोग ICICI बैंक अपने US$7.5 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (GMTN) कार्यक्रम के तहत सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- ICICI Bank Established – 1994
- ICICI बैंक की स्थापना – 1994
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- MD & CEO – Sandeep Bakhshi
- प्रबंध निदेशक एवं CEO – संदीप बख्शी
- Tagline – Hum Hai Na, Khayal Apka
- टैगलाइन – "हम हैं ना, ख़याल आपका"

Ques: Which organisation releases India's monthly credit card spending data?
प्रश्न: भारत में मासिक क्रेडिट कार्ड खर्च के आंकड़े कौन जारी करता है?

A) NPCI / एनपीसीआई

B) SEBI / सेबी

C) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the Reserve Bank of India (RBI), India's credit card spending remained above ₹2 trillion for the second consecutive month, reaching ₹2.01 trillion in June 2026 after ₹2.02 trillion in May 2026.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, जून 2026 में भारत का क्रेडिट कार्ड खर्च ₹2.01 ट्रिलियन रहा, जो मई 2026 के ₹2.02 ट्रिलियन के बाद लगातार दूसरे महीने ₹2 ट्रिलियन से अधिक रहा।

• Overall credit card spending increased by 9.8% year-on-year.

• कुल क्रेडिट कार्ड खर्च में वर्ष-दर-वर्ष 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

• HDFC Bank recorded a 16.2% increase in credit card spending, while SBI Card registered the highest year-on-year growth of 34.4%.

• HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड खर्च में 16.2% की वृद्धि हुई, जबकि SBI Card ने 34.4% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

• RBI data also showed that the total outstanding credit card base increased to 121.6 million cards.

• RBI के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल प्रचलित क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़कर 121.6 मिलियन हो गई।

• The growth was supported by the increasing adoption of UPI-linked RuPay Credit Cards, particularly among public sector banks.

• इस वृद्धि को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में UPI से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्डों के बढ़ते उपयोग से समर्थन मिला।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Credit Card Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
• क्रेडिट कार्ड का नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
• Credit Card Spending Data – Released monthly by RBI
• क्रेडिट कार्ड खर्च के आंकड़े – RBI द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं।
• Major Payment Networks – RuPay, Visa, Mastercard, American Express
• प्रमुख भुगतान नेटवर्क – RuPay, Visa, Mastercard, American Express

---

Ques: Which institution releases India's weekly Foreign Exchange Reserves data?
प्रश्न: भारत के साप्ताहिक विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के आंकड़े कौन जारी करता है?

A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

B) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

C) SEBI / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

D) NABARD / नाबार्ड

E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option B

EXAM Genius

Explanation | व्याख्या:

• According to the Reserve Bank of India (RBI), India's foreign exchange (Forex) reserves increased by $1.08 billion to $676.24 billion for the week ended 17 July 2026.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.08 बिलियन बढ़कर $676.24 बिलियन हो गया।
• The increase was mainly driven by a $4.55 billion rise in Foreign Currency Assets (FCA), which reached $551.06 billion.
• इस वृद्धि का मुख्य कारण Foreign Currency Assets (FCA) में $4.55 बिलियन की

बढ़ोतरी होकर $551.06 बिलियन होना रहा।

• During the same period, gold reserves declined by $3.48 billion to $101.75 billion.

• इसी अवधि में स्वर्ण भंडार $3.48 बिलियन घटकर $101.75 बिलियन रह गया।

• This was the third consecutive weekly increase in India's forex reserves, reflecting stronger external sector stability.

• यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह की वृद्धि रही, जो देश की बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता को दर्शाती है।

• Strong forex reserves help maintain exchange rate stability, strengthen investor confidence and improve India's ability to meet external payment obligations.

• मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने तथा भारत की बाहरी भुगतान क्षमता को मजबूत करने में सहायता करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Foreign Exchange Reserves Data Released By – Reserve Bank of India (RBI)

• विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी करने वाली संस्था – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• India's All-Time Highest Forex Reserves – $728.49 Billion (February 2026)

• भारत का अब तक का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार – $728.49 बिलियन (फरवरी 2026)

Ques: Which two public sector banks are providing ₹5,500 crore debt financing for CtrlS Datacenters' Hyderabad AI data centre project?

प्रश्न: CtrlS Datacenters की हैदराबाद AI डेटा सेंटर परियोजना के लिए ₹5,500 करोड़ का ऋण वित्तपोषण किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया जा रहा है?

A) Punjab National Bank & Bank of Baroda / पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा

B) Canara Bank & Union Bank of India / केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

C) State Bank of India & Central Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल

बैंक ऑफ इंडिया

D) Indian Bank & UCO Bank / इंडियन बैंक एवं यूको बैंक

E) Bank of India & Punjab & Sind Bank / बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब एंड सिंध बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• CtrlS Datacenters has secured ₹5,500 crore in debt financing from State Bank of India (SBI) and Central Bank of India for its upcoming AI-focused data centre campus in Hyderabad.

• CtrlS Datacenters ने हैदराबाद में बनने वाले AI-केंद्रित डेटा सेंटर परिसर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ₹5,500 करोड़ का ऋण वित्तपोषण प्राप्त किया है।

• SBI has sanctioned ₹4,000 crore, while Central Bank of India has sanctioned ₹1,500 crore for the project.

• SBI ने ₹4,000 करोड़ तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ₹1,500 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।

• The financing will initially be structured as Project Finance and will later be converted into a Lease Rental Discounting (LRD) structure.

• शुरुआत में यह वित्तपोषण Project Finance के रूप में होगा, जिसे बाद में Lease Rental Discounting (LRD) संरचना में परिवर्तित किया जाएगा।

• The Hyderabad campus is being developed with a planned capacity of 3.5 GW, making it one of India's largest AI-ready data centre projects.

• हैदराबाद में विकसित किया जा रहा यह परिसर 3.5 GW की नियोजित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी AI-तैयार डेटा सेंटर परियोजनाओं में से एक होगा।

• The project aims to support hyperscalers, cloud service providers and AI platforms by providing advanced digital infrastructure.

• यह परियोजना हाइपरस्केलर्स, क्लाउड सेवा प्रदाताओं तथा AI प्लेटफॉर्म्स को उन्नत डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• CtrlS Datacenters – Founded: 2007
• CtrlS Datacenters – स्थापना: 2007
• Founder & CEO – Sridhar Pinnapureddy
• संस्थापक एवं CEO – श्रीधर पिन्नापुरेड्डी
• Headquarters – Hyderabad, Telangana
• मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
• Business – Hyperscale Data Centres & Cloud Infrastructure
• व्यवसाय – हाइपरस्केल डेटा सेंटर एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर

Ques: Punjab National Bank (PNB) has signed an MoU with which state government to establish India’s first bank-led Quantum Finance Hub?
प्रश्न: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भारत का पहला बैंक-नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता (MoU) किया है?

A) Karnataka / कर्नाटक

B) Telangana / तेलंगाना

C) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश

D) Tamil Nadu / तमिलनाडु

E) Gujarat / गुजरात

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Andhra Pradesh Government and Punjab National Bank (PNB) have signed an MoU to establish the PNB Quantum Finance Hub at the Amaravati Quantum Valley.
• आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अमरावती क्वांटम वैली में PNB क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• According to PNB, it is India's first bank-led Quantum Finance Hub developed

in partnership with a State Government.

• PNB के अनुसार, यह किसी राज्य सरकार के सहयोग से विकसित भारत का पहला बैंक-नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब है।

• The hub will function as a research and innovation centre to explore how Quantum Computing and Artificial Intelligence (AI) can solve complex problems in the banking and financial sector.

• यह हब अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की जटिल समस्याओं के समाधान विकसित किए जाएंगे।

• The initiative aims to promote innovation, strengthen financial technology capabilities, and support the development of next-generation banking solutions.

• इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करना तथा अगली पीढ़ी के बैंकिंग समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Punjab National Bank (PNB) was established in 1894.
• पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की स्थापना 1894 में हुई थी।
• Headquarters – New Delhi.
• मुख्यालय – नई दिल्ली।
• MD & CEO – Ashok Chandra.
• एमडी एवं सीईओ – अशोक चंद्र।
• Andhra Pradesh Capital – Amaravati.
• आंध्र प्रदेश की राजधानी – अमरावती।
• Chief Minister – N. Chandrababu Naidu.
• मुख्यमंत्री – एन. चंद्रबाबू नायडू।
• Governor – S. Abdul Nazeer.
• राज्यपाल – एस. अब्दुल नज़ीर।

Ques: According to RBI norms, a Small Finance Bank must maintain Net NPA at or below what level for two consecutive financial years to become eligible for a Universal Bank Licence?

प्रश्न: RBI के अनुसार, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए पात्र होने हेतु किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का Net NPA लगातार दो वित्तीय वर्षों तक अधिकतम कितना होना चाहिए?

A) 2%
B) 1.5%
C) 1%
D) 0.5%
E) 3%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Capital Small Finance Bank (SFB) reduced its Net Non-Performing Assets (Net NPA) to 1.14% in the quarter ended June 2026, bringing it closer to becoming eligible for a Universal Bank Licence.
• कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) ने जून 2026 तिमाही में अपना नेट NPA घटाकर 1.14% कर लिया है, जिससे वह यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस की पात्रता के और करीब पहुँच गया है।
• As per RBI's "On-Tap" licensing norms, a Small Finance Bank must maintain Net NPA of 1% or below for two consecutive financial years to become eligible for a Universal Bank Licence.
• RBI के "ऑन-टैप" लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए पात्र होने हेतु लगातार दो वित्तीय वर्षों तक 1% या उससे कम Net NPA बनाए रखना आवश्यक है।
• The bank has strengthened its financial position by improving its asset quality, helping it move closer to meeting RBI's licensing criteria.
• बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी (Asset Quality) में सुधार कर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है, जिससे वह RBI के लाइसेंसिंग मानकों को पूरा करने के और करीब पहुँच गया है।
• Besides maintaining Net NPA norms, an SFB must also comply with RBI's capital adequacy and other regulatory requirements before applying for a Universal Bank Licence.

• Net NPA की शर्त के अलावा, किसी SFB को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले RBI की पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) तथा अन्य नियामकीय आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Small Finance Bank (SFB) – Introduced by Reserve Bank of India (RBI) in 2015
• स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 2015 में शुरू किया गया
• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
• नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
• Minimum Paid-up Capital – ₹200 crore
• न्यूनतम चुकता पूंजी – ₹200 करोड़
• Priority Sector Lending (PSL) – Minimum 75% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC)
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) – समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 75%
• Universal Bank Licence Eligibility – Net NPA of 1% or below for two consecutive financial years (along with other RBI norms)
• यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस पात्रता – लगातार दो वित्तीय वर्षों तक 1% या उससे कम Net NPA (अन्य RBI मानकों के साथ)

Ques: The Universal Account Number (UAN) issued to EPFO subscribers consists of how many digits?
प्रश्न: EPFO के सदस्यों को जारी किया जाने वाला Universal Account Number (UAN) कितने अंकों का होता है?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
E) 16

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Labour & Employment has identified 1.18 lakh out of 7.11 lakh dormant EPFO accounts eligible for automatic refunds of balances up to ₹1,000 that had remained unclaimed for years.

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 7.11 लाख निष्क्रिय EPFO खातों में से 1.18 लाख ऐसे खातों की पहचान की है, जिनमें ₹1,000 तक की राशि वर्षों से बिना दावा किए पड़ी थी और अब उन्हें ऑटो रिफंड दिया जाएगा।

• EPFO verified the eligible account holders by linking their active bank account details with their EPF records.

• EPFO ने पात्र खाताधारकों के सक्रिय बैंक खातों का सत्यापन कर उन्हें उनके EPF रिकॉर्ड से जोड़ा।

• The initiative is part of the EPFO 2.01 digital reform programme, which aims to simplify and automate the refund process.

• यह पहल EPFO 2.01 डिजिटल सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को सरल एवं स्वचालित बनाना है।

• The reform builds on the Universal Account Number (UAN) system introduced in 2014 to ensure faster settlement of unclaimed EPF balances without requiring subscribers to submit claims.

• यह सुधार 2014 में शुरू किए गए Universal Account Number (UAN) प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बिना दावा किए पड़े EPF धन का तेजी से एवं स्वतः निपटान सुनिश्चित करना है।

• The Universal Account Number (UAN) is a unique 12-digit number allotted to every EPF member, enabling seamless PF management across different jobs.

• Universal Account Number (UAN) प्रत्येक EPF सदस्य को आवंटित किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, जो विभिन्न नौकरियों में PF प्रबंधन को आसान बनाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) – Established: 1952

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) – स्थापना: 1952

• Headquarters – New Delhi

• मुख्यालय – नई दिल्ली

• Parent Act – Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

• मूल अधिनियम – कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952

• Universal Account Number (UAN) – 12-digit unique number for every EPF member

• Universal Account Number (UAN) – प्रत्येक EPF सदस्य के लिए 12 अंकों का विशिष्ट नंबर

• EPFO 2.01 – Digital reform initiative to simplify and automate EPF services and refunds

• EPFO 2.01 – EPF सेवाओं एवं रिफंड प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने की डिजिटल सुधार पहल

Ques: Shriram Finance may consider applying for which licence in the future if market conditions become favourable?

प्रश्न: अनुकूल बाजार परिस्थितियाँ होने पर Shriram Finance भविष्य में किस लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकती है?

A) Small Finance Bank Licence / स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस

B) Payment Bank Licence / पेमेंट बैंक लाइसेंस

C) Regional Rural Bank Licence / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाइसेंस

D) Universal Bank Licence / यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस

E) Cooperative Bank Licence / सहकारी बैंक लाइसेंस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Shriram Finance has stated that it has no immediate plans to apply for a Universal Bank Licence, but it may reconsider the move in the future if market conditions become favourable and its strategic partner MUFG Bank supports the proposal.

• Shriram Finance ने कहा है कि फिलहाल Universal Bank Licence के लिए आवेदन करने की कोई तत्काल योजना नहीं है, लेकिन अनुकूल बाजार परिस्थितियाँ होने तथा MUFG Bank के समर्थन मिलने पर भविष्य में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

• The company had applied for a banking licence in 2013, but did not pursue it because of regulatory and operational challenges, including CRR, SLR compliance and building a strong CASA deposit base.

• कंपनी ने 2013 में बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन CRR, SLR अनुपालन तथा मजबूत CASA जमा आधार बनाने जैसी नियामकीय एवं परिचालन चुनौतियों के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया।

• According to Executive Vice Chairman Umesh Revankar, MUFG Bank's investment has improved Shriram Finance's credit rating, reduced its borrowing costs, and strengthened its vehicle finance business.

• कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवणकर के अनुसार, MUFG Bank के निवेश से Shriram Finance की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, उधारी लागत घटी है तथा वाहन वित्त (Vehicle Finance) कारोबार मजबूत हुआ है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Shriram Finance Ltd. | श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

• Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
• मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
• Type – Non-Banking Financial Company (NBFC)
• प्रकार – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)
• Chairman – Jugal Kishore Mohapatra
• अध्यक्ष – जुगल किशोर मोहापात्रा

Ques: Which bank was named the World's Best Corporate Bank at the 2026 Global Bank Awards presented by *Global Finance* magazine?

प्रश्न: *Global Finance* पत्रिका द्वारा प्रस्तुत 2026 Global Bank Awards में World's Best Corporate Bank का पुरस्कार किस बैंक को मिला?

A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक

B) Axis Bank / एक्सिस बैंक

C) DBS Bank Limited / डीबीएस बैंक लिमिटेड

D) Santander / सैंटेंडर

E) Standard Chartered Bank India / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• DBS Bank Limited, a Singapore-based multinational banking and financial services corporation, was awarded the World's Best Corporate Bank at the 33rd Global Bank Awards 2026 presented by Global Finance magazine.

• सिंगापुर स्थित बहुराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्था DBS Bank Limited को Global Finance पत्रिका द्वारा आयोजित 33वें Global Bank Awards 2026 में World's Best Corporate Bank का पुरस्कार प्रदान किया गया।

• DBS became the first Southeast Asian bank to win this award since the category was introduced in 2005.

• 2005 में इस श्रेणी की शुरुआत के बाद DBS यह सम्मान प्राप्त करने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला बैंक बन गया।

Other Major Winners | अन्य प्रमुख विजेता

• World's Best Bank: Santander (Spain).
• World's Best Bank: सैंटेंडर (स्पेन)।
• World's Best Consumer Bank: State Bank of India (SBI).
• World's Best Consumer Bank: भारतीय स्टेट बैंक (SBI)।
• Best Banking Product (Savings Account) – India 2026: Bandhan Bank.
• सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग उत्पाद (बचत खाता) – भारत 2026: बंधन बैंक।
• Best SME Bank – India 2026: Axis Bank.
• सर्वश्रेष्ठ SME बैंक – भारत 2026: एक्सिस बैंक।
• Best Wealth Management Bank – India 2026: Standard Chartered Bank India.
• सर्वश्रेष्ठ वेल्थ मैनेजमेंट बैंक – भारत 2026: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• DBS Bank Limited was established in 1968.
• DBS Bank Limited की स्थापना 1968 में हुई थी।
• Headquarters: Singapore.
• मुख्यालय: सिंगापुर।
• DBS stands for Development Bank of Singapore.
• DBS का पूर्ण रूप Development Bank of Singapore है।
• Global Finance is an international financial magazine that presents the Global Bank Awards annually.
• Global Finance एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका है, जो प्रतिवर्ष Global Bank Awards प्रदान करती है।

Ques: Under the RBI's draft amendment on securitisation notes, what is the minimum investment (ticket) size retained for issuance and subsequent transfers?
प्रश्न: RBI के सिक्यूरिटाइजेशन नोट्स संबंधी मसौदा संशोधन के अनुसार, निर्गम एवं बाद के हस्तांतरणों के लिए न्यूनतम निवेश (टिकट साइज) कितना रखा गया है?

A) ₹25 Lakh
B) ₹50 Lakh
C) ₹75 Lakh
D) ₹1 Crore
E) ₹2 Crore

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued the draft Securitisation Transactions (Amendment) Directions, proposing that all securitisation notes issued by commercial banks be issued, held and transferred only in dematerialised (Demat) form.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Securitisation Transactions (Amendment) Directions का मसौदा जारी किया है, जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी सभी सिक्यूरिटाइजेशन नोट्स केवल डीमैट (Demat) रूप में जारी, धारण एवं हस्तांतरित किए जाएंगे।

• The RBI has retained the minimum investment (ticket) size of ₹1 crore for both the initial issuance and all subsequent transfers, applicable per investor.

• RBI ने प्रारंभिक निर्गम तथा बाद के सभी हस्तांतरणों के लिए ₹1 करोड़ का न्यूनतम निवेश (टिकट साइज) बरकरार रखा है, जो प्रत्येक निवेशक पर लागू होगा।

• The draft also proposes aligning the definition of a Public Offer with SEBI regulations.

• मसौदे में सार्वजनिक निर्गम (Public Offer) की परिभाषा को SEBI के नियमों के अनुरूप बनाने का भी प्रस्ताव है।

• The RBI has invited public comments till 27 August 2026, and the revised directions are proposed to come into effect from 1 October 2026.

• RBI ने 27 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं तथा संशोधित नियमों को 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India (RBI) – Established: 1 April 1935
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) – स्थापना: 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Nationalised – 1 January 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

Ques: Which new sector has been included in the revised Index of Core Industries (ICI) with Base Year 2022–23?

प्रश्न: आधार वर्ष 2022–23 वाली संशोधित कोर इंडस्ट्रीज़ सूचकांक (ICI) श्रृंखला में किस नए क्षेत्र को शामिल किया गया है?

A) Steel / इस्पात

B) Cement / सीमेंट

C) Iron Ore / लौह अयस्क

D) Natural Gas / प्राकृतिक गैस

E) Fertilisers / उर्वरक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry (MoCI) has released the revised Index of Core Industries (ICI) with Base Year 2022–23, replacing the earlier 2011–12 base year series.

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoCI) के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने आधार वर्ष 2022–23 वाली संशोधित कोर इंडस्ट्रीज़ सूचकांक (ICI) श्रृंखला जारी की है, जिसने 2011–12 आधार वर्ष वाली पुरानी श्रृंखला का स्थान लिया है।

• Iron Ore has been included as a new core industry in the revised series.

• संशोधित श्रृंखला में लौह अयस्क (Iron Ore) को नई कोर इंडस्ट्री के रूप में शामिल किया गया है।

• With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9.

• इसके साथ ही कोर उद्योगों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है।

• In the Coal sector, only Raw Coal has been retained. Coal Middlings and Washed Coal have been excluded to avoid double counting, as both are derived from Raw Coal.

• कोयला क्षेत्र में केवल कच्चे कोयले (Raw Coal) को रखा गया है। Coal Middlings और Washed Coal को दोहरी गणना (Double Counting) से बचने के लिए हटाया गया है, क्योंकि दोनों कच्चे कोयले से ही प्राप्त होते हैं।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Index of Core Industries (ICI) measures the performance of India's key infrastructure sectors.

• कोर इंडस्ट्रीज़ सूचकांक (ICI) भारत के प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापता है।

• Released by: Office of the Economic Adviser (OEA), DPIIT, Ministry of Commerce & Industry.

• जारीकर्ता: आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

• The revised ICI now covers 9 core industries.

• संशोधित ICI अब 9 कोर उद्योगों को शामिल करता है।

• These are: Coal (Raw Coal), Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilisers, Steel, Cement, Electricity, and Iron Ore.

• ये हैं: कोयला (कच्चा कोयला), कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली तथा लौह अयस्क।

Ques: Who has been appointed as the Chief Business Officer (CBO) of SBI Mutual Fund?

प्रश्न: SBI म्यूचुअल फंड का मुख्य व्यवसाय अधिकारी (Chief Business Officer - CBO) किसे नियुक्त किया गया है?

A) D. P. Singh / डी. पी. सिंह

B) Ashwani Bhatia / अश्विनी भाटिया

C) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार

D) Manish Mehta / मनीष मेहता

E) Challa Sreenivasulu Setty / चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• SBI Mutual Fund, India's largest Asset Management Company (AMC), has appointed Manish Mehta as its Chief Business Officer (CBO).

• भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) SBI Mutual Fund ने मनीष मेहता

को अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी (Chief Business Officer - CBO) नियुक्त किया है।

• Manish Mehta joined SBI Mutual Fund after completing a 15-year tenure (2010–2025) at Kotak Mahindra Asset Management Company.

• मनीष मेहता ने Kotak Mahindra Asset Management Company में 15 वर्ष (2010–2025) तक कार्य करने के बाद SBI Mutual Fund जॉइन किया है।

• At Kotak Mahindra AMC, he last served as Joint President & National Head – Sales, Marketing and Digital Business.

• Kotak Mahindra AMC में वे Joint President एवं National Head – Sales, Marketing and Digital Business के पद पर कार्यरत थे।

• With his extensive experience in sales, distribution, marketing and digital business, he is expected to play a key role in strengthening SBI Mutual Fund's future business growth.

• बिक्री, वितरण, विपणन एवं डिजिटल व्यवसाय में उनके व्यापक अनुभव से SBI Mutual Fund के व्यवसाय विस्तार और भविष्य की विकास रणनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SBI Mutual Fund – Established: 1987
• SBI म्यूचुअल फंड – स्थापना: 1987
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Type – Asset Management Company (AMC)
• प्रकार – एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC)
• Parent Institution – State Bank of India (SBI)
• मूल संस्था – भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

Ques: According to the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), what was India's share of global GDP (PPP) in 2025?
प्रश्न: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अनुसार, 2025 में वैश्विक GDP (PPP) में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी?

A) 6.5%

B) 7.4%
C) 8.2%
D) 9.7%
E) 10.3%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to a working paper published by the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), India accounted for 8.2% of the world's Gross Domestic Product (GDP) based on Purchasing Power Parity (PPP) in 2025.
• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा प्रकाशित एक कार्यपत्र (Working Paper) के अनुसार, 2025 में क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर वैश्विक GDP में भारत की हिस्सेदारी 8.2% थी।
• The working paper is titled "The World in Purchasing Power Parity (PPP): Trends since 1992."
• इस कार्यपत्र का शीर्षक "The World in Purchasing Power Parity (PPP): Trends since 1992" है।
• India's share in global GDP (PPP) increased from 3.2% in 1992 to 8.2% in 2025 and is projected to reach 9.7% by 2030.
• वैश्विक GDP (PPP) में भारत की हिस्सेदारी 1992 में 3.2% से बढ़कर 2025 में 8.2% हो गई है और 2030 तक 9.7% होने का अनुमान है।
• India now accounts for 10.3% of global savings and 10.8% of global investment, ranking second and third globally, respectively.
• भारत अब वैश्विक बचत का 10.3% तथा वैश्विक निवेश का 10.8% हिस्सा रखता है, जिससे वह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
• By 2030, China and India together are projected to account for 30.1% of global GDP (PPP), highlighting Asia's growing economic influence.
• 2030 तक चीन और भारत मिलकर वैश्विक GDP (PPP) का 30.1% हिस्सा रखने का अनुमान है, जो एशिया के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• EAC-PM stands for Economic Advisory Council to the Prime Minister.
• EAC-PM का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है।
• Chairman: Prof. S. Mahendra Dev.
• अध्यक्ष: प्रो. एस. महेंद्र देव।
• Composition: 3 Full-Time Members and 11 Part-Time Members.
• संरचना: 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 11 अंशकालिक सदस्य।
• PPP (Purchasing Power Parity) compares the purchasing power of different countries' currencies by considering the cost of a common basket of goods and services.
• PPP (क्रय शक्ति समता) विभिन्न देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की तुलना वस्तुओं और सेवाओं की समान टोकरी की लागत के आधार पर करता है।

Ques: Who has been appointed by the Delhi High Court as the Official Liquidator of Paytm Payments Bank Ltd.?
प्रश्न: दिल्ली उच्च न्यायालय ने Paytm Payments Bank Ltd. का आधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) किसे नियुक्त किया है?

A) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार

B) Dinesh Kumar Khara / दिनेश कुमार खारा

C) Girikumar M. Nair / गिरिकुमार एम. नायर

D) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

E) Challa Sreenivasulu Setty / चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Delhi High Court has appointed former State Bank of India (SBI) Chief General Manager (CGM) Girikumar M. Nair as the Official Liquidator of Paytm Payments Bank Ltd.
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मुख्य महाप्रबंधक

(CGM) गिरिकुमार एम. नायर को Paytm Payments Bank Ltd. का आधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) नियुक्त किया है।

• The appointment follows the cancellation of Paytm Payments Bank's banking licence by the Reserve Bank of India (RBI).

• यह नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद की गई है।

• The Official Liquidator will exercise powers under the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013 to conduct the liquidation process.

• आधिकारिक परिसमापक Banking Regulation Act, 1949 तथा Companies Act, 2013 के प्रावधानों के तहत बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

• The Liquidator will supervise the winding-up of the bank, settlement of claims, and compliance with all legal procedures.

• परिसमापक बैंक के परिसमापन, दावों के निपटान तथा सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेंगे।

• The appointment is aimed at ensuring an orderly liquidation process while protecting the interests of depositors and creditors.

• इस नियुक्ति का उद्देश्य जमाकर्ताओं एवं लेनदारों के हितों की रक्षा करते हुए बैंक का सुव्यवस्थित परिसमापन सुनिश्चित करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Paytm Payments Bank Ltd. – Established: 2017
• Paytm Payments Bank Ltd. – स्थापना: 2017
• Type – Payments Bank
• प्रकार – पेमेंट्स बैंक
• Headquarters – Noida, Uttar Pradesh
• मुख्यालय – नोएडा, उत्तर प्रदेश

Ques: Which type of bank account is exempt from Minimum Average Balance (MAB) penalty?

प्रश्न: किस प्रकार का बैंक खाता न्यूनतम औसत शेष (MAB) जुर्माने से मुक्त होता है?

A) Current Account / चालू खाता

B) Salary Account / वेतन खाता

C) Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) / बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA)

D) Fixed Deposit Account / सावधि जमा (FD) खाता

E) Recurring Deposit Account / आवर्ती जमा (RD) खाता

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to a written reply in the Rajya Sabha by Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary, banks collected more than ₹26,170 crore as Minimum Average Balance (MAB) penalties during FY23–FY26.

• राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित उत्तर के अनुसार, बैंकों ने FY23–FY26 के दौरान न्यूनतम औसत शेष (MAB) न रखने पर ₹26,170 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला।

• HDFC Bank, Axis Bank and ICICI Bank together collected more than ₹11,000 crore, exceeding the combined MAB penalty collections of all 12 Public Sector Banks (PSBs) during the same period.

• HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने मिलकर ₹11,000 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला, जो इसी अवधि में सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की संयुक्त वसूली से अधिक है।

• HDFC Bank alone collected more than ₹5,600 crore as MAB penalties.

• केवल HDFC बैंक ने ही ₹5,600 करोड़ से अधिक का न्यूनतम बैलेंस जुर्माना वसूला।

• The Government clarified that Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs), including PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts, are exempt from Minimum Average Balance penalties.

• सरकार ने स्पष्ट किया कि Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs), जिनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाते भी शामिल हैं, न्यूनतम बैलेंस जुर्माने से मुक्त हैं।

• Banks are required to follow RBI guidelines before levying Minimum Average Balance charges on customers.

• ग्राहकों पर न्यूनतम बैलेंस शुल्क लगाने से पहले बैंकों को RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

• Launch Date – 28 August 2014
• शुभारंभ – 28 अगस्त 2014
• Launched By – Prime Minister Narendra Modi
• शुभारंभकर्ता – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
• Nodal Ministry – Ministry of Finance (Department of Financial Services)
• नोडल मंत्रालय – वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)
• Objective – Financial Inclusion through Zero-Balance Bank Accounts and access to banking services
• उद्देश्य – शून्य शेष बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता
• Account Type – Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Account with Zero Minimum Balance
• खाता प्रकार – शून्य न्यूनतम शेष वाला बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाता
• Free Facility – RuPay Debit Card with Accident Insurance Cover up to ₹2 lakh (eligible accounts)
• निःशुल्क सुविधा – रुपे डेबिट कार्ड एवं ₹2 लाख तक दुर्घटना बीमा (पात्र खातों के लिए)
• Overdraft Facility – Up to ₹10,000 (subject to eligibility)
• ओवरड्राफ्ट सुविधा – ₹10,000 तक (पात्रता के अनुसार)
• Direct Benefit Transfer (DBT) – Government subsidies and welfare benefits are directly transferred into PMJDY accounts
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) – सरकारी सब्सिडी एवं कल्याणकारी लाभ सीधे PMJDY खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं

Latest Progress (As on 15 July 2026) | नवीनतम प्रगति (15 जुलाई 2026 तक)

• Total Jan Dhan Accounts – 58.77 crore
• कुल जन धन खाते – 58.77 करोड़
• Total Deposits – ₹3,12,413.78 crore

• कुल जमा राशि – ₹3,12,413.78 करोड़
• Women Account Holders – 32.75 crore
• महिला खाताधारक – 32.75 करोड़

Ques: The Asian Development Bank (ADB) approved an $850 million loan to support which flagship scheme of India?
प्रश्न: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 850 मिलियन डॉलर का ऋण भारत की किस प्रमुख योजना के समर्थन हेतु स्वीकृत किया है?

A) PM-KUSUM Yojana / पीएम-कुसुम योजना

B) National Solar Mission / राष्ट्रीय सौर मिशन

C) PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana / पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

D) Smart Cities Mission / स्मार्ट सिटीज मिशन

E) AMRUT Mission / अमृत मिशन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Asian Development Bank (ADB) has approved $1.85 billion in financing for India. This includes a $1 billion loan for the Urban Transformation and Investment Program and an $850 million loan for the second phase of the Accelerating Affordable and Inclusive Rooftop Solar Systems Development Program.
• एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के लिए 1.85 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसमें 1 अरब डॉलर शहरी परिवर्तन एवं निवेश कार्यक्रम तथा 850 मिलियन डॉलर Accelerating Affordable and Inclusive Rooftop Solar Systems Development Program के दूसरे चरण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
• The $1 billion Urban Transformation and Investment Program will strengthen the Urban Challenge Fund, improve urban governance, integrated planning and the financial capacity of Urban Local Bodies (ULBs).

• 1 अरब डॉलर का Urban Transformation and Investment Program, Urban Challenge Fund को मजबूत करेगा तथा शहरी प्रशासन, एकीकृत योजना एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय क्षमता में सुधार करेगा।

• The urban programme will also provide $3 million in technical assistance to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

• शहरी कार्यक्रम के तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 3 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

• The $850 million loan will support the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana through the second phase of the rooftop solar systems development programme.

• 850 मिलियन डॉलर का ऋण प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को रूफटॉप सोलर सिस्टम विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के माध्यम से समर्थन देगा।

• The funding will help finance at least 3.5 million rooftop solar installations, strengthen electricity distribution networks, improve digital monitoring systems and promote private sector participation.

• इस वित्तीय सहायता से कम-से-कम 35 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, डिजिटल निगरानी प्रणाली में सुधार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Asian Development Bank (ADB) – Established: 19 December 1966
• एशियाई विकास बैंक (ADB) – स्थापना: 19 दिसंबर 1966
• Headquarters – Manila, Philippines
• मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
• President – Masato Kanda
• अध्यक्ष – मसातो कांडा
• Members – 69 (49 Asia-Pacific & 20 outside the region)
• सदस्य – 69 (49 एशिया-प्रशांत एवं 20 अन्य क्षेत्र)
• India joined ADB – 1966
• भारत ADB का सदस्य बना – 1966

Ques: BNP Paribas Cardif has signed an agreement to acquire approximately 26% stake in IndiaFirst Life Insurance from which company?
प्रश्न: BNP Paribas Cardif ने IndiaFirst Life Insurance में लगभग 26% हिस्सेदारी किस कंपनी से खरीदने के लिए समझौता किया है?

A) Warburg Pincus / वारबर्ग पिंकस

B) Blackstone / ब्लैकस्टोन

C) KKR / केकेआर

D) Temasek Holdings / टेमासेक होल्डिंग्स

E) Carlyle Group / कार्लाइल ग्रुप

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• French insurance company BNP Paribas Cardif has signed an agreement to acquire approximately 26% stake in IndiaFirst Life Insurance from Warburg Pincus.
• फ्रांस की बीमा कंपनी BNP Paribas Cardif ने IndiaFirst Life Insurance में लगभग 26% हिस्सेदारी Warburg Pincus से खरीदने के लिए समझौता किया है।
• Warburg Pincus, a global private equity firm, currently holds this stake through its affiliate Carmel Point Investments India Private Limited.
• Warburg Pincus, जो एक वैश्विक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, अपनी सहयोगी कंपनी Carmel Point Investments India Private Limited के माध्यम से यह हिस्सेदारी रखती है।

Shareholding Pattern after the Deal | सौदे के बाद शेयरधारित

- Bank of Baroda : Around **65%**
- BNP Paribas Cardif : Around **26%**
- Union Bank of India : Around **9%**

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• IndiaFirst Life Insurance was established in 2009.
• IndiaFirst Life Insurance की स्थापना 2009 में हुई थी।
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• Bank of Baroda is the promoter and largest shareholder of IndiaFirst Life Insurance.
• बैंक ऑफ बड़ौदा IndiaFirst Life Insurance का प्रवर्तक (Promoter) और सबसे बड़ा शेयरधारक है।
• BNP Paribas Cardif is the insurance business of BNP Paribas Group, headquartered in Paris, France.
• BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Group का बीमा व्यवसाय है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

Ques: Who has been appointed as the new Chief Financial Officer (CFO) of LIC?
प्रश्न: LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) किसे नियुक्त किया गया है?

A) Sunil Agrawal / सुनील अग्रवाल
B) Siddhartha Mohanty / सिद्धार्थ मोहंती
C) Shatmanyu Shrivastava / शतमन्यु श्रीवास्तव
D) Varadarajan Muthuvenkataraman / वरदराजन मुथुवेंकटरमण
E) M. Nagaraju / एम. नागराजू

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Life Insurance Corporation of India (LIC) has appointed Shatmanyu Shrivastava as its new Chief Financial Officer (CFO), replacing Sunil Agrawal.
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने शतमन्यु श्रीवास्तव को नया मुख्य वित्तीय

अधिकारी (CFO) नियुक्त किया है। उन्होंने सुनील अग्रवाल का स्थान लिया है।

• Sunil Agrawal resigned after serving as LIC's CFO for more than four years.

• सुनील अग्रवाल ने चार वर्ष से अधिक समय तक CFO के रूप में कार्य करने के बाद इस्तीफा दिया।

• LIC has also appointed Varadarajan Muthuvenkataraman as its new Chief Risk Officer (CRO).

• LIC ने वरदराजन मुथुवेंकटरमण को नया मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer - CRO) नियुक्त किया है।

• Both appointments became effective from 28 July 2026.

• दोनों नियुक्तियाँ 28 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।

• Before becoming CFO, Shatmanyu Shrivastava served as Executive Director (Enterprise Risk Management) & Chief Risk Officer (CRO).

• CFO बनने से पहले शतमन्यु श्रीवास्तव Executive Director (Enterprise Risk Management) एवं Chief Risk Officer (CRO) के पद पर कार्यरत थे।

• Before his appointment as CRO, Varadarajan Muthuvenkataraman served as Additional Executive Director (Enterprise Risk Management).

• CRO बनने से पहले वरदराजन मुथुवेंकटरमण Additional Executive Director (Enterprise Risk Management) के पद पर कार्यरत थे।

• The appointments mark an important leadership transition in LIC's finance and enterprise risk management functions.

• ये नियुक्तियाँ LIC के वित्त एवं एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) – Established: 1 September 1956

• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) – स्थापना: 1 सितंबर 1956

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• Chairperson & CEO – Shri R. Doraiswamy

• अध्यक्ष एवं CEO – श्री आर. दोरईस्वामी

Ques: Ashok Leyland has signed an MoU with which bank for providing vehicle financing solutions?
प्रश्न: अशोक लेलैंड ने वाहन वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है?

A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

C) UCO Bank / यूको बैंक

D) Canara Bank / केनरा बैंक

E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Ashok Leyland, the flagship commercial vehicle company of the Hinduja Group, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with UCO Bank to provide vehicle financing solutions.
• हिंदुजा समूह की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने वाहन वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूको बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• Under the partnership, customers purchasing Ashok Leyland trucks and buses will receive customised and flexible financing solutions.
• इस साझेदारी के तहत अशोक लेलैंड के ट्रक एवं बस खरीदने वाले ग्राहकों को अनुकूलित एवं लचीले वित्तीय समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे।
• The collaboration aims to make commercial vehicle ownership easier by improving access to vehicle finance.
• इस सहयोग का उद्देश्य वाहन वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाकर वाणिज्यिक वाहनों का स्वामित्व आसान बनाना है।
• The initiative will support the commercial vehicle ecosystem and strengthen Ashok Leyland's customer outreach across India.
• यह पहल वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र को समर्थन देगी तथा पूरे भारत में अशोक लेलैंड के ग्राहक आधार को मजबूत करेगी।

• The partnership is expected to improve financial accessibility for transport operators and businesses while boosting vehicle sales.

• इस साझेदारी से परिवहन संचालकों एवं व्यवसायों के लिए वित्तीय पहुँच बेहतर होगी तथा कंपनी की वाहन बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

UCO Bank

• Established – 1943
• स्थापना – 1943
• Headquarters – Kolkata, West Bengal
• मुख्यालय – कोलकाता, पश्चिम बंगाल
• MD & CEO – Rajendra Kumar Saboo
• MD एवं CEO – राजेंद्र कुमार साबू
• Tagline – Honours Your Trust
• टैगलाइन – Honours Your Trust

Ashok Leyland

• Established – 1948
• स्थापना – 1948
• Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
• मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
• Parent Group – Hinduja Group
• मूल समूह – हिंदुजा समूह

Ques: SBI Life Insurance Company Limited has become the Principal Partner of the Indian contingent by signing a strategic partnership with which organization?

प्रश्न: SBI Life Insurance Company Limited ने किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी कर भारतीय दल का Principal Partner बनने की घोषणा की है?

A) Sports Authority of India (SAI) / भारतीय खेल प्राधिकरण

B) Paralympic Committee of India (PCI) / भारतीय पैरालंपिक समिति

C) Indian Olympic Association (IOA) / भारतीय ओलंपिक संघ

D) Athletics Federation of India (AFI) / भारतीय एथलेटिक्स महासंघ

E) Hockey India / हॉकी इंडिया

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SBI Life Insurance Company Limited has entered into a strategic partnership with the Paralympic Committee of India (PCI), becoming the Principal Partner of the Indian contingent for the 2026 para sports season.

• SBI Life Insurance Company Limited ने भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है और 2026 पैरा खेल सत्र के लिए भारतीय दल का Principal Partner बना है।

• Under this partnership, SBI Life Insurance will serve as the Official Life Insurance Partner of the Indian contingent at:

- Commonwealth Para Games 2026 – Glasgow, Scotland
- Asian Para Games 2026 – Aichi–Nagoya, Japan

• इस साझेदारी के तहत SBI Life Insurance निम्न आयोजनों में भारतीय दल का Official Life Insurance Partner होगा:

- कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 – ग्लासगो, स्कॉटलैंड

- एशियाई पैरा गेम्स 2026 – आइची–नागोया, जापान

• Earlier, SBI Life Insurance had also partnered with India's para athletes during the 2024 Paris Paralympic Games held in Paris, France.
• इससे पहले SBI Life Insurance ने पेरिस, फ्रांस में आयोजित 2024 पैरालंपिक खेलों के दौरान भी भारतीय पैरा खिलाड़ियों का सहयोग किया था।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Paralympic Committee of India (PCI) is the apex body responsible for promoting and managing para sports in India.
• भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) भारत में पैरा खेलों के संचालन एवं प्रोत्साहन के लिए सर्वोच्च संस्था है।

• Commonwealth Para Games 2026 will be held in Glasgow, Scotland.
• कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा।

• Asian Para Games 2026 will be held in Aichi–Nagoya, Japan.
• एशियाई पैरा गेम्स 2026 का आयोजन आइची–नागोया, जापान में होगा।

• SBI Life Insurance Company Limited was established in 2001 and is headquartered in Mumbai, Maharashtra.
• SBI Life Insurance Company Limited की स्थापना 2001 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।

Ques: The Government's recent ₹12,604 crore Government Securities (G-Sec) Buyback Auction was primarily aimed at what?
प्रश्न: सरकार द्वारा हाल ही में किए गए ₹12,604 करोड़ के सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बायबैक **का मुख्य उद्देश्य क्या था?**

A) Increasing Repo Rate / रेपो दर बढ़ाना
B) Retiring short-term Government Securities and managing liquidity /

अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को समय से पहले वापस खरीदना एवं तरलता का प्रबंधन करना

C) Issuing new currency notes / नई मुद्रा जारी करना

D) Increasing CRR / CRR बढ़ाना

E) Providing loans to banks / बैंकों को ऋण प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India accepted bids worth ₹12,604 crore in the latest Government Securities (G-Sec) Buyback Auction against the notified amount of ₹20,000 crore.

• भारत सरकार ने ₹20,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले नवीनतम सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बायबैक नीलामी में ₹12,604 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकार किए।

• Investors offered Government Securities worth ₹16,959 crore, out of which bids worth ₹12,604 crore were accepted.

• निवेशकों ने ₹16,959 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियाँ पेश कीं, जिनमें से ₹12,604 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

• The Reserve Bank of India (RBI) accepted the highest amount under the 7.33% GS 2026 bond.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7.33% GS 2026 बॉन्ड के तहत सबसे अधिक राशि स्वीकार की।

• RBI also bought back portions of 8.15% GS 2026, 5.74% GS 2026, and 8.24% GS 2027 securities.

• RBI ने 8.15% GS 2026, 5.74% GS 2026 तथा 8.24% GS 2027 सरकारी प्रतिभूतियों का भी बायबैक किया।

• The buyback aims to retire short-term Government Securities before maturity, improve public debt management, and maintain adequate liquidity in the bond market.

• इस बायबैक का उद्देश्य अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को परिपक्वता (Maturity) से पहले वापस खरीदना, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा बॉन्ड बाजार में पर्याप्त तरलता बनाए रखना है।

Ques: The **London Stock Exchange (LSE) has launched LSE 24**, **a new platform primarily designed for what purpose?**
प्रश्न: लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) द्वारा शुरू किया गया **LSE 24** प्लेटफ़ॉर्म मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है?

A) After-hours trading for global investors / वैश्विक निवेशकों के लिए आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग
B) Cryptocurrency trading / क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग
C) Commodity derivatives trading / कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग
D) Bond settlement services / बॉन्ड सेटलमेंट सेवाएँ
E) IPO listing platform / आईपीओ लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The London Stock Exchange (LSE) has announced the launch of LSE 24, a new after-hours trading platform designed to provide near-continuous trading for global investors.
• लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) ने LSE 24 नामक एक नया आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को लगातार ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करना है।
• LSE 24 will allow trading from 5:00 PM to 7:50 AM (London Time), significantly extending the exchange's trading hours.
• LSE 24 पर शाम 5:00 बजे से सुबह 7:50 बजे (लंदन समय) तक ट्रेडिंग की जा सकेगी, जिससे एक्सचेंज के ट्रेडिंग समय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• Client testing of the platform is expected to begin by the end of 2026.
• इस प्लेटफ़ॉर्म का क्लाइंट परीक्षण 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
• In its initial phase, LSE 24 will support trading in Exchange-Traded Products (ETPs), including Exchange-Traded Funds (ETFs).
• प्रारंभिक चरण में LSE 24 पर Exchange-Traded Products (ETPs), जिनमें Exchange-Traded Funds (ETFs) शामिल हैं, की ट्रेडिंग की जाएगी।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• London Stock Exchange (LSE) was established in 1801.
• लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) की स्थापना 1801 में हुई थी।
• Headquarters: London, United Kingdom.
• मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
• CEO: Julia Hoggett.
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): जूलिया होगेट।
• ETF (Exchange-Traded Fund) is an investment fund that is traded on a stock exchange like ordinary shares.
• ETF (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) एक निवेश फंड है, जिसकी खरीद-बिक्री सामान्य शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर होती है।

Ques: The RBI's concessional US Dollar–Rupee Forex Swap Facility for PSUs is mainly intended to support which type of borrowing?
प्रश्न: RBI की रियायती US Dollar–Rupee Forex Swap Facility मुख्य रूप से PSUs को किस प्रकार के उधार के लिए सहायता प्रदान करती है?

A) Treasury Bills (T-Bills) / ट्रेजरी बिल्स (टी-बिल्स)

B) External Commercial Borrowings (ECBs) / एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECBs)

C) Sovereign Gold Bonds (SGBs) / सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs)

D) Masala Bonds / मसाला बॉन्ड्स

E) Commercial Papers (CPs) / कमर्शियल पेपर्स (CPs)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Public Sector Undertakings (PSUs) have requested the Reserve Bank of India (RBI) to extend its concessional US Dollar–Rupee Forex Swap Facility by three

months beyond **31 December 2026** to support overseas fund raising through **External Commercial Borrowings (ECBs)**.

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) ने RBI से **31 दिसंबर 2026** के बाद उसकी रियायती **US Dollar–Rupee Forex Swap Facility** को **3 महीने** बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि वे **External Commercial Borrowings (ECBs)** के माध्यम से विदेशी धन जुटा सकें।

• The forex swap facility helps PSUs reduce **currency hedging costs** on long-term ECBs having a **minimum average maturity of three years**, making overseas borrowing cheaper and more attractive.

• यह सुविधा PSUs के **कम-से-कम 3 वर्ष की औसत परिपक्वता (Minimum Average Maturity)** वाले दीर्घकालिक ECBs पर **मुद्रा हेजिंग (Currency Hedging)** की लागत कम करती है, जिससे विदेशी ऋण लेना अधिक सस्ता और आकर्षक बनता है।

• PSUs have sought the extension because many of them raise overseas funds during the **last quarter of the financial year** for major infrastructure and development projects.

• PSUs ने इस सुविधा के विस्तार का अनुरोध इसलिए किया है क्योंकि कई सार्वजनिक उपक्रम **वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही** में बड़े बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी धन जुटाते हैं।

• Extending the facility is expected to encourage **higher foreign currency mobilisation** and support **capital expenditure (CapEx)** across public sector enterprises.

• इस सुविधा के विस्तार से **विदेशी मुद्रा में अधिक धन जुटाने** तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के **पूंजीगत व्यय** (CapEx) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Ques: At what coupon rate did SBI raise ₹4,691 crore through its Additional Tier-1 (AT-1) bond issue?

प्रश्न: SBI ने अपने Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्ड इश्यू के माध्यम से ₹4,691 करोड़ किस कूपन दर पर जुटाए?

A) 7.25%
B) 7.50%
C) 7.75%
D) 8.00%
E) 8.25%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India (SBI) raised ₹4,691 crore through its first Additional Tier-1 (AT-1) bond issue of the financial year 2026–27.

• भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के अपने पहले Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्ड इश्यू के माध्यम से ₹4,691 करोड़ जुटाए।

• The perpetual bonds carry a coupon (interest) rate of 7.75% and include a call option after five years, with subsequent call options on every anniversary thereafter.

• ये Perpetual Bonds हैं, जिन पर 7.75% कूपन (ब्याज) दर निर्धारित की गई है तथा 5 वर्ष बाद Call Option और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर कॉल विकल्प उपलब्ध रहेगा।

• The issue had a base size of ₹3,000 crore with a greenshoe option of ₹2,000 crore and received bids worth more than twice the base issue size from institutional investors.

• इस इश्यू का बेस साइज ₹3,000 करोड़ तथा ₹2,000 करोड़ का ग्रीनशू विकल्प था। इसे संस्थागत निवेशकों से बेस इश्यू से दो गुना से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं।

• The bond issue will strengthen SBI's regulatory capital and support future business growth.

• यह बॉन्ड इश्यू SBI की नियामकीय पूंजी (Regulatory Capital) को मजबूत करेगा तथा भविष्य की ऋण वृद्धि और व्यवसाय विस्तार को समर्थन देगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Additional Tier-1 (AT-1) Bonds | अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड

• AT-1 Bonds are perpetual debt instruments issued by banks to strengthen their capital base.

• AT-1 बॉन्ड बैंकों द्वारा अपनी पूंजी को मजबूत करने के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी (Perpetual) ऋण साधन हैं।

• They generally have a call option after five years, but no fixed maturity date.

• इनमें सामान्यतः 5 वर्ष बाद Call Option होता है, लेकिन कोई निश्चित परिपक्वता

(Maturity Date) नहीं होती।

• AT-1 Bonds qualify as Additional Tier-1 Capital under the Basel III banking norms.

• Basel III मानकों के तहत AT-1 बॉन्ड Additional Tier-1 Capital का हिस्सा माने जाते हैं।

Ques: Which company received IRDAI's fourth insurance licence approval in the calendar year 2026?

प्रश्न: वर्ष 2026 में IRDAI द्वारा जारी चौथा बीमा लाइसेंस किस कंपनी को मिला?

A) Kiwi General Insurance / किवी जनरल इंश्योरेंस

B) Prudential HCL Health Insurance / प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस

C) Allianz Jio Reinsurance / एलियांज जियो रीइंश्योरेंस

D) ProTec General Insurance / प्रोटेक जनरल इंश्योरेंस

E) SBI General Insurance / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has granted a Certificate of Registration to ProTec General Insurance Limited, allowing it to commence general insurance business in India.

• भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ProTec General Insurance Limited को पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) प्रदान किया है, जिससे कंपनी भारत में सामान्य बीमा (General Insurance) का व्यवसाय शुरू कर सकेगी।

• ProTec General Insurance is a joint venture between the M Pallonji Group and True North's Divya Sehgal. This is the fourth insurance licence approved by IRDAI in the calendar year 2026.

• ProTec General Insurance, M Pallonji Group और True North की Divya Sehgal

का संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) है। यह वर्ष 2026 में IRDAI द्वारा स्वीकृत चौथा बीमा लाइसेंस है।

• Earlier in 2026, IRDAI had granted licences to Kiwi General Insurance, Prudential HCL Health Insurance, and Allianz Jio Reinsurance.

• वर्ष 2026 में इससे पहले IRDAI ने Kiwi General Insurance, Prudential HCL Health Insurance तथा Allianz Jio Reinsurance को भी लाइसेंस प्रदान किए थे।

• According to IRDAI, these approvals reflect strong investor confidence and support the reforms under the Sabka Bima Sabki Raksha (SBSR) Act.

• IRDAI के अनुसार, ये मंजूरियाँ बीमा क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास तथा Sabka Bima Sabki Raksha (SBSR) Act के तहत किए गए सुधारों को दर्शाती हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) – Established: 1999

• भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) – स्थापना: 1999

• Headquarters – Hyderabad

• मुख्यालय – हैदराबाद

• Chairperson – Ajay Seth

• अध्यक्ष – अजय सेठ

• Established under – IRDA Act, 1999

• गठन – IRDA Act, 1999 के तहत

Ques: Why did SEBI cancel the registrations of 10 Research Analysts?

प्रश्न: SEBI ने 10 रिसर्च एनालिस्ट्स का पंजीकरण किस कारण रद्द किया?

A) Insider Trading / इनसाइडर ट्रेडिंग

B) Market Manipulation / बाजार में हेरफेर

C) Failure to pay mandatory renewal fee / अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान न करना

D) Money Laundering / मनी लॉन्ड्रिंग

E) Tax Evasion / कर चोरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) cancelled the registrations of 10 Research Analysts for failing to pay the mandatory renewal fee required to keep their registration certificates valid.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क (Renewal Fee) का भुगतान न करने पर 10 रिसर्च एनालिस्ट्स का पंजीकरण रद्द कर दिया।

• The action was taken under the SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008, after the entities failed to comply despite receiving multiple notices from the regulator.

• यह कार्रवाई SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008 के तहत की गई, क्योंकि संबंधित संस्थाओं ने नियामक द्वारा कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया।

• The decision reinforces SEBI's commitment to ensuring that all registered intermediaries comply with regulatory requirements and maintain valid registration while operating in the securities market.

• यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है कि पूंजी बाजार में कार्यरत सभी पंजीकृत मध्यस्थ नियामकीय प्रावधानों का पालन करें तथा अपना पंजीकरण वैध बनाए रखें।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) – Established: 12 April 1988
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) – स्थापना: 12 अप्रैल 1988
• Statutory Status – 30 January 1992 (SEBI Act, 1992)
• वैधानिक दर्जा – 30 जनवरी 1992 (SEBI अधिनियम, 1992)
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय

Ques: The Central Government has permitted the Reserve Bank of India (RBI) to initially print how many polymer banknotes for field trials?
प्रश्न: केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को प्रारंभिक चरण में फील्ड ट्रायल के लिए कितने पॉलिमर बैंकनोट छापने की अनुमति दी है?

A) 1 billion pieces / 1 अरब नोट

B) 1.5 billion pieces / 1.5 अरब नोट

C) 2 billion pieces / 2 अरब नोट

D) 2.5 billion pieces / 2.5 अरब नोट

E) 3 billion pieces / 3 अरब नोट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government has permitted the Reserve Bank of India (RBI) to initially print 2 billion polymer banknotes for field trials.
• केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को प्रारंभिक चरण में फील्ड ट्रायल के लिए 2 अरब पॉलिमर बैंकनोट छापने की अनुमति दी है।

• Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed the Lok Sabha that:
1 billion ₹10 polymer notes, and
1 billion ₹20 polymer notes
will be printed for field trials and later issued for regular circulation after successful testing.
• वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि:
₹10 के 1 अरब पॉलिमर नोट, तथा
₹20 के 1 अरब पॉलिमर नोट
पहले फील्ड ट्रायल के लिए छापे जाएंगे और परीक्षण सफल होने के बाद नियमित प्रचलन में जारी किए जाएंगे।

• The proposal was sent by the RBI, with the recommendation of its Central Board, to the Central Government under Section 25 of the Reserve Bank of

India Act, 1934.

• यह प्रस्ताव RBI ने अपने केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board) की सिफारिश पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार को भेजा था।

• In 2012, the Government had also approved a field trial of 1 billion ₹10 polymer notes in five cities.

• 2012 में भी सरकार ने 5 शहरों में ₹10 के 1 अरब पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी थी।

Ques: Google Pay recently launched its second co-branded credit card in partnership with which company?

प्रश्न: Google Pay ने हाल ही में अपना दूसरा Co-branded Credit Card किस कंपनी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

C) Axis Bank / एक्सिस बैंक

D) SBI Card / एसबीआई कार्ड

E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option D

EXAM Genius

Explanation | व्याख्या:

• Google Pay has partnered with SBI Card to launch the Google Pay Flex SBI Card, its second co-branded credit card in India within a year.

• Google Pay ने SBI Card के साथ साझेदारी कर Google Pay Flex SBI Card लॉन्च किया, जो भारत में एक वर्ष के भीतर उसका दूसरा सह-ब्रांडेड (Co-branded) क्रेडिट कार्ड है।

• The contactless card will be available on both RuPay and Visa card networks, offering users flexible payment and digital-first credit solutions.

• यह कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड RuPay और Visa दोनों कार्ड नेटवर्क पर उपलब्ध होगा

तथा ग्राहकों को डिजिटल और लचीले भुगतान (Flexible Payment) की सुविधा देगा।

• Google Pay has also introduced a Gemini AI-powered conversational feature in its app to help users analyse spending patterns, understand savings, and learn financial concepts such as credit scores.

• Google Pay ने अपने ऐप में Gemini AI आधारित संवादात्मक (Conversational) फीचर भी जोड़ा है, जिससे उपयोगकर्ता अपने खर्चों का विश्लेषण, बचत की जानकारी तथा क्रेडिट स्कोर जैसे वित्तीय विषयों को समझ सकेंगे।

• Earlier, in December 2025, Google Pay had launched its first co-branded credit card with Axis Bank on the RuPay network.

• इससे पहले दिसंबर 2025 में Google Pay ने Axis Bank के साथ अपना पहला Co-branded Credit Card RuPay नेटवर्क पर लॉन्च किया था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

SBI Card | एसबीआई कार्ड

• Established – 1998

• स्थापना – 1998

• Headquarters – Gurugram, Haryana

• मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा

Google Pay | गूगल पे

• Launched in India – 2017 (as Tez)

• भारत में शुरुआत – 2017 (Tez के रूप में)

• Rebranded as Google Pay – 2018

• Google Pay के रूप में रीब्रांड – 2018

• Parent Company – Google LLC

• मूल कंपनी – Google LLC

Ques: YES BANK has signed an MoU with which company to collaborate in institutional capital solutions?

प्रश्न: YES BANK ने संस्थागत पूंजी समाधान (Institutional Capital Solutions) के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है?

A) BlackRock / ब्लैकरॉक

B) Capital Stack / कैपिटल स्टैक

C) KFin Technologies / केफिन टेक्नोलॉजीज़

D) NSE IX / एनएसई आईएक्स

E) SIDBI / सिडबी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• YES BANK has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Capital Stack, an institutional capital solutions platform, to establish a framework for collaboration in institutional capital solutions.

• YES BANK ने Capital Stack के साथ संस्थागत पूंजी समाधान (Institutional Capital Solutions) के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• Under the agreement, Capital Stack will use its institutional network, market expertise and transaction structuring capabilities to identify, evaluate, structure and facilitate financing opportunities aligned with YES BANK's strategic priorities.

• इस समझौते के तहत Capital Stack अपने संस्थागत नेटवर्क, बाजार विशेषज्ञता तथा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग क्षमता का उपयोग करते हुए YES BANK की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप वित्तपोषण (Financing) के अवसरों की पहचान, मूल्यांकन, संरचना और सुविधा प्रदान करेगा।

• The partnership aims to strengthen institutional financing, improve access to capital solutions, and support the execution of large and complex financial transactions.

• इस साझेदारी का उद्देश्य संस्थागत वित्तपोषण को मजबूत करना, पूंजी समाधान (Capital Solutions) तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना तथा बड़े एवं जटिल वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• YES BANK – Founded: 2004
• YES BANK – स्थापना: 2004
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• MD & CEO – Vinay Muralidhar Tonse
• प्रबंध निदेशक एवं CEO – विनय मुरलीधर टोंसे

Ques: Union Bank of India paid a dividend of ₹2,853.33 crore to the Government of India for which financial year?
प्रश्न: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को ₹2,853.33 करोड़ का लाभांश किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया?

A) FY23
B) FY24
C) FY25
D) FY26
E) FY27

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Union Bank of India presented a dividend cheque of ₹2,853.33 crore to the Government of India for the financial year 2025–26 (FY26).
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए भारत सरकार को ₹2,853.33 करोड़ का लाभांश (Dividend) चेक सौंपा।
• The dividend cheque was handed over by Aseesh Pandey, Managing Director & CEO of Union Bank of India, to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.
• यह लाभांश चेक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं CEO असीश पांडे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा।
• The dividend reflects the bank's improved financial performance and contributes to the Government's non-tax revenue through dividends from public sector enterprises.

• यह लाभांश बैंक के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से सरकार को प्राप्त गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) में योगदान देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Union Bank of India – Founded: 11 November 1919
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – स्थापना: 11 नवंबर 1919
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• MD & CEO – Aseesh Pandey
• प्रबंध निदेशक एवं CEO – असीश पांडे
• Tagline – Good People to Bank With
• टैगलाइन – Good People to Bank With

Ques: Which city recorded the highest RBI Ombudsman complaint rate during FY 2024–25?
प्रश्न: FY 2024–25 में RBI लोकपाल शिकायत दर में कौन-सा शहर सबसे ऊपर रहा?

A) Mumbai / मुंबई

B) Bengaluru / बेंगलुरु

C) Chennai / चेन्नई

D) Chandigarh / चंडीगढ़

E) Hyderabad / हैदराबाद

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Chandigarh recorded the highest complaint rate under the Reserve Bank of India (RBI) Integrated Ombudsman Scheme during FY 2024–25, with a

complaint rate more than 4.5 times the national average.

• वित्त वर्ष 2024–25 में रिज़र्व बैंक के एकीकृत लोकपाल (Integrated Ombudsman) योजना के तहत चंडीगढ़ में शिकायतों की दर देश के औसत से 4.5 गुना से अधिक रही, जो पूरे देश में सबसे अधिक थी।

• Across India, the total number of complaints received under the RBI Ombudsman mechanism increased by 13.55% to 1.33 million (13.3 lakh) in FY25 compared with the previous year.

• पूरे देश में RBI लोकपाल तंत्र के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 13.55% बढ़कर 13.3 लाख (1.33 मिलियन) हो गई।

• Loans and advances emerged as the largest complaint category in FY25.

• FY25 में ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances) सबसे बड़ी शिकायत श्रेणी रही।

• For the first time since FY21, private sector banks received more complaints than public sector banks, while complaints against NBFCs also increased.

• FY21 के बाद पहली बार निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अधिक रहीं तथा NBFCs के विरुद्ध शिकायतों में भी वृद्धि दर्ज की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Integrated Ombudsman Scheme – Launched: 12 November 2021

• RBI एकीकृत लोकपाल योजना – शुरुआत: 12 नवंबर 2021

• Launched by – Reserve Bank of India (RBI)

• प्रारंभकर्ता – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• Objective – To provide a single, free and simplified grievance redressal mechanism for customers of banks, NBFCs and payment system operators.

• उद्देश्य – बैंकों, NBFCs तथा भुगतान प्रणाली संचालकों के ग्राहकों को एकीकृत, सरल एवं निःशुल्क शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराना।

Ques: Who has been appointed as the Non-Executive Vice Chairman of Kotak Investment Banking (KIB)?

प्रश्न: कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग (KIB) के Non-Executive Vice Chairman के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Uday Kotak / उदय कोटक

B) Ashok Vaswani / अशोक वासवानी

C) Ramesh Srinivasan / रमेश श्रीनिवासन

D) Sourav Mallik / सौरव मलिक

E) V. Jayasankar / वी. जयसांकर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Kotak Investment Banking (KIB) has appointed Ramesh Srinivasan as its Non-Executive Vice Chairman for a three-year term, effective 1 August 2026.
• कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग (KIB) ने रमेश श्रीनिवासन को 1 अगस्त 2026 से तीन वर्ष के लिए Non-Executive Vice Chairman नियुक्त किया है।
• In his new role, he will advise the management on strategic matters and key institutional relationships.
• अपनी नई भूमिका में वे प्रबंधन को रणनीतिक मामलों एवं प्रमुख संस्थागत संबंधों पर सलाह देंगे।
• The board has also appointed V. Jayasankar and Sourav Mallik as Managing Directors & Co-Chief Executive Officers (Co-CEOs) of Kotak Investment Banking.
• बोर्ड ने वी. जयसांकर और सौरव मलिक को मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Co-CEO) भी नियुक्त किया है।
• The appointments are aimed at strengthening Kotak Investment Banking's leadership and supporting its long-term strategic growth.
• इन नियुक्तियों का उद्देश्य कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नेतृत्व को मजबूत करना तथा दीर्घकालिक रणनीतिक विकास को गति देना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Kotak Investment Banking (KIB) | कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग
• Parent Company – Kotak Mahindra Bank
• मूल कंपनी – कोटक महिंद्रा बैंक
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Chairman – Uday Kotak
• चेयरमैन – उदय कोटक

Ques: Under RBI's revised bulk deposit framework, banks can now offer differential interest rates based on which factor?
प्रश्न: RBI के संशोधित बल्क डिपॉजिट ढांचे के तहत अब बैंक किस आधार पर अलग-अलग ब्याज दरें दे सकते हैं?

A) Repo Rate / रेपो दर

B) Inflation Rate / मुद्रास्फीति दर

C) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Run-off Risk / लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) रन-ऑफ जोखिम

D) Cash Reserve Ratio (CRR) / नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

E) Bank Rate / बैंक दर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• RBI has revised deposit interest rate rules, requiring banks to publish all deposit interest rates, including bulk deposits, in advance on their websites to improve transparency.
• RBI ने जमा ब्याज दरों के नियमों में संशोधन करते हुए बैंकों को बल्क डिपॉजिट सहित सभी जमा ब्याज दरें अग्रिम रूप से अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया है।
• Banks can now offer different interest rates on bulk deposits based on Liquidity Coverage Ratio (LCR) run-off risk, while ensuring there is no discrimination for similar deposits.
• अब बैंक Liquidity Coverage Ratio (LCR) के रन-ऑफ जोखिम के आधार पर बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें दे सकेंगे, लेकिन समान प्रकार की जमाओं के साथ

भेदभाव नहीं कर सकेंगे।

• The revised directions will come into effect from 1 October 2026, giving banks time to implement the new framework.

• संशोधित दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, जिससे बैंकों को नई व्यवस्था लागू करने का समय मिलेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) | लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR)

• Introduced under – Basel III Framework

• प्रारंभ – बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत

• Purpose – Ensures banks maintain sufficient High-Quality Liquid Assets (HQLA) to meet short-term liquidity needs.

• उद्देश्य – बैंकों को अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियाँ (HQLA) बनाए रखने को सुनिश्चित करना।

Ques: What was the combined net profit of India's Public Sector Banks (PSBs) during FY 2025–26?

प्रश्न: वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का संयुक्त शुद्ध लाभ (Net Profit) कितना रहा?

A) ₹1.68 lakh crore / ₹1.68 लाख करोड़

B) ₹1.82 lakh crore / ₹1.82 लाख करोड़

C) ₹1.98 lakh crore / ₹1.98 लाख करोड़

D) ₹2.10 lakh crore / ₹2.10 लाख करोड़

E) ₹2.25 lakh crore / ₹2.25 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's **Public Sector Banks (PSBs)** recorded their **highest-ever combined net profit** of **₹1.98 lakh crore** during **FY 2025–26**.

• भारत के **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs)** ने **वित्त वर्ष 2025–26** में **₹1.98 लाख करोड़** का अब तक का **सर्वाधिक संयुक्त शुद्ध लाभ** दर्ज किया।

• The aggregate **net profit increased by 11.1% year-on-year**, marking the **fourth consecutive year of profitability** for PSBs.

• संयुक्त **शुद्ध लाभ में 11.1% की वार्षिक वृद्धि** हुई, जो **लगातार चौथा लाभकारी वर्ष** रहा।

• The **combined business** of PSBs reached **₹283.3 lakh crore** as of **31 March 2026**, registering **12.8% annual growth**.

• **31 मार्च 2026** तक PSBs का **कुल व्यवसाय ₹283.3 लाख करोड़** रहा, जिसमें **12.8% की वार्षिक वृद्धि** दर्ज की गई।

Key Financial Indicators | प्रमुख वित्तीय संकेतक

- Aggregate net profit - ₹1.98 lakh crore
- Growth in net profit - 11.1%
- Operating profit - ₹3.21 lakh crore
- Total business - ₹283.3 lakh crore
- Total deposits - ₹156.3 lakh crore
- Gross advances - ₹127 lakh crore
- Gross NPA ratio - 1.93%
- Net NPA ratio - 0.39%
- Capital Adequacy Ratio—CRAR - 16.6%

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Gross NPA (GNPA) represents the total value of loans classified as non-performing before making provisions.

• सकल NPA (GNPA) उन ऋणों का कुल मूल्य है जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets) बन चुके हैं।

• Net NPA (NNPA) is the Gross NPA minus provisions made by banks.

• शुद्ध NPA (NNPA) = सकल NPA – बैंकों द्वारा किए गए प्रावधान (Provisions)।

• CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) measures a bank's capital

strength and its ability to absorb financial losses.

• CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा संभावित वित्तीय जोखिमों को वहन करने की क्षमता को दर्शाता है।

Ques: SEBI has agreed to settle all pending cases of which stock exchange, clearing the way for its Mega IPO?

प्रश्न: SEBI ने किस स्टॉक एक्सचेंज के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने पर सहमति दी है, जिससे उसके मेगा IPO का रास्ता साफ हो गया है?

A) BSE
B) MCX
C) National Stock Exchange (NSE)
D) India INX
E) NSE IFSC

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has agreed to settle all pending cases against the National Stock Exchange (NSE), including the co-location and dark fibre cases, for ₹1,491.21 crore.

• SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सभी लंबित मामलों, जिनमें को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले शामिल हैं, का ₹1,491.21 करोड़ में निपटारा करने पर सहमति दी है।

• The settlement removes the last major regulatory hurdle, clearing the way for NSE's long-awaited Mega IPO.

• इस समझौते से अंतिम प्रमुख नियामकीय बाधा दूर हो गई है, जिससे NSE के लंबे समय से लंबित मेगा IPO का रास्ता साफ हो गया है।

• After SEBI issues the final settlement order, pending court cases are expected to be withdrawn, and NSE plans to raise over ₹26,000 crore through its IPO.

• SEBI द्वारा अंतिम सेटलमेंट आदेश जारी होने के बाद लंबित न्यायिक मामले वापस

लिए जाने की संभावना है तथा NSE अपने IPO के माध्यम से ₹26,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना बना रहा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

National Stock Exchange (NSE) | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
- Established – 1992
- स्थापना – 1992
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Market Regulator – SEBI (Securities and Exchange Board of India)
- बाजार नियामक – SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)

Ques: ICICI Prudential Mutual Fund purchased its stake in Go Digit General Insurance from which investor?
प्रश्न: ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने Go Digit General Insurance में अपनी हिस्सेदारी किस निवेशक से खरीदी?

A) SoftBank / सॉफ्टबैंक

B) Peak XV Partners / पीक XV पार्टनर्स

C) Blackstone / ब्लैकस्टोन

D) Temasek Holdings / टेमासेक होल्डिंग्स

E) Warburg Pincus / वारबर्ग पिंकस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- ICICI Prudential Mutual Fund acquired 57.21 lakh shares (around 0.62% stake) in Go Digit General Insurance through a block deal worth about ₹139 crore.

• ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने Go Digit General Insurance में लगभग 57.21 लाख शेयर (करीब 0.62% हिस्सेदारी) ₹139 करोड़ के ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदे।
• The shares were purchased from Peak XV Partners at an average price of ₹243 per share on the National Stock Exchange (NSE).
• यह हिस्सेदारी Peak XV Partners से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹243 प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदी गई।
• Following the transaction, Go Digit's shares gained more than 1% during trading.
• इस लेन-देन के बाद Go Digit के शेयरों में कारोबार के दौरान 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Go Digit General Insurance | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस
• Established – 2016
• स्थापना – 2016
• Headquarters – Bengaluru, Karnataka
• मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक
• Founder – Kamesh Goyal
• संस्थापक – कामेश गोयल

Ques: Which price index will be used by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) as a deflator for GDP estimates, replacing the Wholesale Price Index (WPI) wherever applicable?
प्रश्न: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आकलन में, जहाँ लागू हो, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर किस मूल्य सूचकांक का उपयोग डिफ्लेटर के रूप में किया जाएगा?

A) Consumer Price Index (CPI) / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
B) Output Producer Price Index (Output PPI) / आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (Output PPI)
C) Retail Price Index (RPI) / खुदरा मूल्य सूचकांक (RPI)

D) Food Price Index (FPI) / खाद्य मूल्य सूचकांक (FPI)

E) Industrial Production Index (IIP) / औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) announced that the Output Producer Price Index (Output PPI) will replace the Wholesale Price Index (WPI) as the deflator for quarterly and annual GDP estimates wherever applicable.

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने घोषणा की है कि जहाँ लागू होगा, वहाँ त्रैमासिक एवं वार्षिक GDP आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (Output PPI) का उपयोग डिफ्लेटर के रूप में किया जाएगा।

• The Output PPI will improve the accuracy of real GDP growth measurement by reducing distortions in GDP estimates.

• Output PPI के उपयोग से वास्तविक GDP वृद्धि के आकलन की सटीकता बढ़ेगी तथा GDP अनुमानों में होने वाली विकृतियाँ कम होंगी।

• The revised GDP series has updated the base year from 2011–12 to 2022–23.

• संशोधित GDP श्रृंखला में आधार वर्ष 2011–12 से बदलकर 2022–23 कर दिया गया है।

• The new GDP methodology adopts the double deflation approach, which separately adjusts output prices and input prices to obtain more accurate value-added estimates.

• नई GDP पद्धति में डबल डिफ्लेशन (Double Deflation) पद्धति अपनाई गई है, जिसमें आउटपुट और इनपुट कीमतों को अलग-अलग समायोजित कर अधिक सटीक सकल मूल्य वर्धन (Value Added) का अनुमान लगाया जाता है।

• Double deflation is considered an internationally accepted method for improving the measurement of real economic growth.

• डबल डिफ्लेशन वास्तविक आर्थिक वृद्धि के अधिक सटीक आकलन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य पद्धति मानी जाती है।